International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 11, November- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

नोटबंदी के दो वर्ष

डॉ उमेश प्रताप सिंह
एसोसिएट प्रोफ़ेसर, अर्थशास्त्र विभाग
इविंग क्रिश्चियन महाविद्यालय
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

सार

नोट बंदी का प्रभाव मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था और समाज पर सकारात्मक पड़ा है। समाज में और लोगों पर यह भय क गलत कार्य करने पर पकड़े जा सकते हैं नोट बंदी की एक बड़ी सफलता है । रिटेल व्यवसाय का 90 प्रतिशत से अ धक नगदी होता था , उसे नियंत्रित करने में नोट बंदी की एक महत्वपूर्ण भू मका हो सकती थी। सर्फ वही पैसा काला धन नहीं है जो सरकारी कर से बच गया बल्कि जो पैसा अर्थव्यवस्था में से बाहर चला गया वह भी काला धन है। नोट बंदी से लगभग 40 प्रतिशतनकदी जो क अर्थव्यवस्था में निष्क्रिय पड़ा था वह चलन में आ गया। हां यह जरूर है क बैंक और बु लयन के अ धकारियों के भ्रष्टाचार के कारण लगभग सारा ही कालाधन बैं कंग सस्टम में आ गया। भ्रष्टाचार का जिस तरह से संस्थानिकरण हुआ है उसके कारण नोट बंदी का अपे क्षत परिणाम नहीं आ पाया। जब तक लोगों के माइंडसेट में परिवर्तन नहीं होता या उन में नैतिकता का समावेश नहीं होता है तब तक इस तरह के कड़े कदमों का ठोस परिणाम सामने नहीं आ सकता। नोट बंदी से पहले सरकार को सबसे अ धक रोजगार प्रदान करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र और खुदरा और छोटे व्यापारियों पर इसके प्रभाव के संदर्भ में गंभीरता से सोचना चाहिए था।

मुख्य शब्द : नोट बंदी, काला धन, मुद्रा पूर्ति, एमएसएमई

दो साल पहले 8 नवंबर 2016 की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान कया था। उन्होंने यह कहकर देश-दुनिया को चौंका दिया क तब चलन में रहे 500 और 1,000 रुपये के नोट रात 12 बजे से अवैध हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों ने वत्त मंत्रालय द्वारा 7 नवंबर 2016 को प्राप्त प्रस्ता वत ड्राफ्ट में ₹1000 और ₹500 कीनोट को वापस लए जाने के संदर्भ में कहा था क काला धन रोकने और नकली मुद्रा को चलन में प्रतिबं धत करने के लहाज से एक अच्छा कदम है। परंतु साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी थी क वमुद्रीकरण वर्तमान वत्तीय वर्ष में जीडीपी पर अल्प काल में नकारात्मक प्रभाव डालेगा। काला धन रोकने के संदर्भ में आरबीआई बोर्ड का कहना था क ज्यादातर काला धन नगदी के रूप में नहीं है बल्कि यह वास्त वक वास्त वक क्षेत्र संपत्तियों के रूप में , जैसे

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 11, November- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

सोना, रियल स्टेट आदि के रुप में है और वमुद्रीकरण से इस प्रकार की संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर डॉ रघुराम राजन ने अभी हाल ही में अपने एक महत्वपूर्ण लेक्चर में कहा क वमुद्रीकरण और जीएसटी जैसे दो लगातार झटकों से भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्ध पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और भारत की समृद धी दर में गरावट आई जब क वैश्विक अर्थव्यवस्था में समृद्ध बढ़ने की ओर अग्रसर थे। आरबीएल बैंक की सीईओ रहीं मीरा सान्याल ने नोटबंदी पर अभी 8 नवम्बर को आई अपनी कताब में लखा है की नोटबंदी जैसे कदम से ना सर्फ देश की संवृद्ध रुक गयी बल्कि अनावश्यक रूप से देश के प्रत्येक नागरिक को परेशानी उठानी पड़ी ।

उसी समय मैंने अपने एक आलेख में कहा था क सरकार द्वारापुराने 500-1000 रूपये के नोटों को चलन से बाहर करना (वमुद्रीकरण) एक अभूतपूर्व और साह सक कदम है ।अभूतपूर्व इस लए क्यों क 500-1000 रूपये के नोट चलन के कुल नोटों का 86 प्रतिशतसे अ धक हैं, और देश में इतने बड़े पैमाने पर वमुद्रीकरण इससे पहले कभीनहीं हुआ।साह सकइस लए , क्यों क इससे पछले 2 वर्षों की सुस्ती केबाद कुछ महीने से सुधर रही अर्थव्यवस्था को फर से धक्का लगेगा और 3-6 महीने या कुछ ज्यादा समय के लए मंदी की आहट आ सकती है!और यह भी तय था क कुछ समय के लए आम आदमी की आ र्थक मुश्किलें बढेंगी। यह झटके अप्रत्या शत नहीं थे ।

काला धन सफ़ेद हो गया!

वत्त वर्ष 2016-17 की सालाना रिपोर्ट में आरबीआई ने बताया क अवैध घो षत 15.44 लाख करोड़ रुपये में से 15.31 लाख करोड़ रुपये बैं कंग सस्टम में वापस आ गए। यानी , अवैध घो षत कुल 99.3 प्रतिशतनोट बैंकों में जमा कर दिए गए जब क 10,720 करोड़ रुपये मूल्य के महज 0.7 प्रतिशतनोटों का ही कुछ पता नहीं चल पाया। नोट बंदीके समय यह बात कही जा रही थी जितनी मुद्रा को चलन से बाहर कया गया है उसका कम से कम 10 प्रतिशत तो बैं कंग सस्टम में नहीं आना है परंतु लगभग 99 प्रतिशत मुद्रा वापस आ गई. यह दावा प्रधानमंत्री ने भी कया था क जो काली मुद्रा बैंकों में जमा नहीं हो पाएगी सरकार को प्राप्त होने से सरकार का बड़ा फायदा हो सकता है । इस लए इस बिंदु को लेकर मोदी सरकार की काफी आलोचना की गई क कुछ भी कालाधन सरकार के पास नहीं आया और नोटबंदी असफल रही है ।

वस्तुतः आशा के वपरीत लगभग 99 प्रतिशतपैसा रिजर्व बैंक के पास आ जाना नोट बंदी की असफलता नहीं है। क्यों क पैसा बैंक में आने के बाद सफेद नहीं हो गया अभी भी उसकी अकाउंटेबि लटी तय होना बाकी है। वह पैसा जो क अर्थव्यवस्था में ज्यादातर निष्क्रिय पड़ा था, वह आरबीआई के रिकॉर्ड में आ गया । सरकार ने बहुत से ऐसे अ धक आय जमा करने वाले लोगों से पूछताछ भी की और कार्यवाही भी कय है। जो पैसा अब रिकॉर्ड में आ गया हैउस से उसके चोरी करने वाले लोगों के नाम सामने आयेंगे और अगर इमानदारी से कार्रवाई हो उनका बचना आसान नहीं होगा ।बेनामी कानून के अंतर्गत

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 11, November- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

आय के स्रोत के ववरण को जानने के लए राजस्व वभाग ने 10,000 से अ धक लोगों को नोटिस दिया है।वास्तव में काला धन और भ्रष्टाचार कोई ऐसी समस्या नहीं है जो क छड़ी घुमाते ही समाप्त हो जाये।इसके लए अनेक स्तरों पर लम्बे समय तक ठोस और साह सक क़दमों की जरुरत है ।

कर राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि

वमुद्रीकरणकेबाद कर राजस्व में महत्वपूर्ण वृ द्ध हुई जो क नोट बंदी की एक बड़ी सफलता है । करदाता का आधारजो क औसतन 6.2 म लयन नवंबर 2010 से 16 के बीच में था वह बढ़कर नवंबर 2016 17 के दौरान 10.1 मलीयन हो गया । 2017 18 के दौरान 6.2 करोड़ आयकर रिटर्न भरी गई जो क 2016 17 के 5.1 करोड़ से 1.3 करोड़ अ धक है । प्रत्यक्ष कर संग्रह 2016-17 में 14 प्रतिशत से अ धक और 2017-18 में 18 प्रतिशत बढ़ा है। प्रत्यक्ष कर बॉयंसी (जीडीपी वृ द्ध में बदलाव पर कर राजस्व वृ द्ध की प्रति क्रया) की दर वर्ष 2017-18 में बढ़कर 1.81 हो गई है , जो 2015-16 में 0.8 थी। आयकर रिटर्न भरने वाले लोगों की संख्या (पांच लाख रुपये से अ धक कुल सालाना आय) में वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान 13 से 25 प्रतिशत की अच्छी वृ द्ध दर्ज की गई है। हालां क अभी 2017-18 के आयकर रिटर्न के आंकड़े संक लत नहीं कए गए हैं। इन तीन वर्षों में केवल 2.5 लाख रुपये से कम आय श्रेणी वाले और 2016-17 में 5 लाख रुपये से कम आय वाले लोगों के रिटर्न भरने में कमी दर्ज की गई है।

वत्त वर्ष 2017-18 के लए आयकर रिटर्न दा खल करने की अंतिम ति थ 31 अगस्त की समाप्ति पर प्राप्त कुल रिटर्न की संख्या 71 प्रतिशतबढ़कर 5.42 करोड़ रही। अगस्त 2018 तक दा खल आयकर रिटर्न की संख्या 5.42 करोड़ है जो 31 अगस्त 2017 में 3.17 करोड़ थी। यह दा खल रिटर्न की संख्या में 70.86 प्रतिशतवृ द्ध को दर्शाता है।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया क वत्त वर्ष 2017-18 में कर संग्रह बढ़कर रेकॉर्ड 10.03 करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच गया।

अर्थव्यवस्था में समृद्धि लौटी

नोटबंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की समृ द्ध इधर में क मयां है जो क नोटबंदी का एक स्वाभा वक प्रभाव था और यह कोई अप्रत्या शत नहीं था जनवरी-मार्च 2017 भारतीय अर्थव्यवस्था की वृ द्ध दर कम होकर 6.1 प्रतिशत रह गई जो क पछले 2 वर्षों में सबसे कम थी । परंतु अर्थव्यवस्था अपने समृ द्ध के पुराने स्तरों पर लौट आइ है और अभी भी यह वश्व की सबसे तेजी से वृ द्ध करने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुईहै।

कंपनियों की आय में वृद्धि

नोट बंदी के ठीक पहले अर्थव्यवस्था में तेजी के लक्षण दिखाई दिए थे और कंपनियों की आय में वृ द्ध होना शुरू हो गया था परंतु नोटबंदी के बाद कंपनियों के आय पर प्रभाव पड़ा । नोट बंदी से पहले कमो डटी की उच्च कीमतों में कमी के कारण अर्थव्यवस्था बेहतर होने की तरफ बढ़ रही थी । नोटबंदी के बाद यही स्थिति पलट गई । वशेष रूप से छोटे व्यापारियों और उद्य मयों को भारी नुकसान हुआ और नोटबंदी के बाद के पहले 4 महीनों में उनके व्यवसाय में 50 प्रतिशत से अ धक की जबरदस्त

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 11, November- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

कमी हुई ।उसके बाद जीएसटी आने के कारण भी सबसे अ धक यहीं तक का प्रभा वत हुआ क्यों क सबसे अ धक नगदी लेने यही करते थे । परन्तु नोटबंदी के डेढ़ वर्ष बाद इनकी स्थिति में अब सुधार दिख रहा है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवेश बढ़े

नोटबंदी के बाद बैं कंग सस्टम में बड़ी मात्रा में नकदी आया । इस कारण बैंकों ने जमा दरों पर ब्याज दरों में कमी कर दी ।साव ध जमा पर ब्याज दरें कम होने से लोगों का झुकाव मु चुअल फंड वनिवेश की ओर बढ़ा इस दौरान मुचल फंड की एसआईपी में महत्वपूर्ण वृ द्ध वशेष रूप से छोटे शहरों में एसआईपी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा । मु चुअलफंड में निवेशजो क सतंबर 2016 में 2.74 लाख करोड़ रुपए था सतंबर 2017 में बढ़कर 3.7 9 लाख करोड़ हो गया, अर्थात इसमें 38.7 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृ द्ध हुई।

रियल स्टेट की स्थिति में सुधार

नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट क्षेत्र में कीमतों में काफी गरावट आई और वशेष रूप से हाउ संग क्षेत्र काफी प्रभा वत हुआ। रियल एस्टेट निर्माण में बड़े पैमाने पर नगदी और काले धन का प्रयोग होता रहा है। साथहीरेरा के प्रावधानों और जीएसटी से भी रियल स्टेट पर काफी प्रभाव पड़ा ।परंतु रेरा के कारण प्रॉपर्टी के लेन-देन में पारद र्शता बड़ी और यह खरीदारों के लए काफीमददगार साबित हुआ।इस लए अब रियल स्टेट की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है और भारतीय रियल एस्टेट में प्राइवेट इक्विटी निवेश में काफी तेजी से वृ द्ध हुई है।

नगदी लेन-देन मेंकमी

नोट बंदी के कारण अर्थव्यवस्था में नगदी लेन-देन में कमी आई है कैशलेस लेनदेन बड़ा है और अर्थव्यवस्था में पारद र्शता बड़ी है । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब डजिटल इं डया को बढ़ावा मलने के कारण लोगों की मान सकता में काफी बदलाव आया है।

वर्ष 2012 में नैशनल पेमेंट काउं सल ऑफ इं डया (NPCI) द्वारा तैयार कया गया पेमेंट सस्टम रुपे भारतीय पेमेंट्स मार्केट पर दोनों अमेरिकी कंपनियों का दबदबा खत्म कर चुका है। NPCI डेटा से पता चलता है क इस वर्ष अगस्त महीने में रुपे कार्ड्स से 4 करोड़ 96 लाख ट्रांजैक्शन के जरिए 62 अरब 90 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। रुपे की सफलता ने मास्टकार्ड जैसी वदेशी दिग्गजों की नींद हराम कर दी। मास्टरकार्ड ने अमेरिकी सरकार से कहा है क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अपने पेमेंट नेटवर्क रुपे को बढ़ावा देने के लए राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं।

10 साल पहले 1 करोड़ 40 लाख डेबिट कार्ड्स ही थे जो अब बढ़कर 1 अरब तक पहुंच चुके हैं। गौरतलब है क NPCI का अपना अलग पेमेंट मोड है जिसे UPI के नाम से जाना जाता है। अगस्त महीन में 31 करोड़ 20 लाख बार इस पेमेंट मोड के इस्तेमाल से 5 अरब 42 करोड़ 10 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ था। यानी, इसकी लोक प्रयता बेहद तेज रफ्तार से बढ़ रही है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 11, November- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बेहद तेज वृद्ध हुई। सतंबर 2018 तक भीमऐप का ऐंड्रॉयड वर्जन 3 करोड़ 55 लाख जब क आईओएस वर्जन 17 लाख डाउनलोड हो चुका था। आंकड़े बताते हैं क 18 अक्टूबर 2018 तक भीएम ऐप से 8,206.37 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 18 लाख 27 हजार ट्रांजैक्शन हुए।

नोटबंदी का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी काफी प्रभाव पड़ा क्यों क ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः नगदी पर ही आधारित थी ।हालां क नोटबंदी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कैशलेस ट्रांजैक्शन महत्वपूर्ण रूप से बड़ा है । वशेष रूप से युवाओं में रुझान बहुत तेजी से पनपा है । परंतु अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अ धकतर लेनदेन नगदी में ही होते हैं और इस कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था नोट बंदी से काफी प्रभा वत हुई है । नकदी की कमी के कारण नोटबंदी के बाद नगदी रहित लेनदेन में महत्वपूर्ण वृद्ध हुई । भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में भी नगदी रहित लेनदेन बड़ा वशेषकर युवाओं में डेबिट कार्ड और भीम एप फॉर साथी नेट बैं कंग प्रति रुझान बहुत तेजी से बड़ा है।

कारोबारी सुगमता में सुधार

वश्व बैंक के कारोबारी सुगमता सूचकांक की 2019 की रैं कंग में भारत ने 2018 की तुलना में 23 स्थानों का सुधार कया है।कारोबारी सुगमता रैं कंग में शीर्ष 100 देशों के क्लब में पहले ही शा मल हो चुका भारत वर्ष 2019 की सूची में 77वें स्थान पर पहुंच चुका है। मोदी सरकार को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी क 190 देशों में भारत उन दो देशों में शा मल है जिन्होंने लगातार दो वर्ष इस सूची में सुधार कया है। इससे पहले की बात करें तो वर्ष 2017 में भारत ने केवल एक स्थान का सुधार कया था ले कन अगले वर्ष 2018 में इसने 30 स्थानों का सुधार कया। अब ताजा सुधार के बाद भारत 77वें स्थान पर आ गया है। इस तरह भारत ने महज दो वर्षों में ही अंतरराष्ट्रीय कारोबार की इस सौंदर्य प्रतिस्पद्र्धा में 53 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है। भारत वदेशी मुद्रा प्रवाह आक र्षत करने के मामले में दसवें स्थान पर है।

यह कोई छोटीमोटी उपलब्धि नहीं है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के ऐन पहले वाले वर्षों के दौरान इस सूचकांक में भारत का प्रदर्शन निरंतर खराब होता जा रहा था। वर्ष 2012 में 131वें स्थान से फसलकर हम 2014 में 142वें स्थान पर आ गए थे। तब से अब तक तेज और सकारात्मक बदलाव देखने को मले हैं। प्रधानमंत्री मोदी तथा उनकी सरकार को इसका पूरा श्रेय भी दिया जाना चाहिए। वर्ष 2014 में जहां सभी ब्रिक्स देश हमसे आगे थे , वहीं 2019 में हम द क्षण अफ्रीका (82), और ब्राजील (109) से आगे हैं और चीन (46) और रूस (31) के साथ अंतर तेजी से कम हो रहा है। भारत अब द क्षण ए शया का सबसे बढिया रैं कंग वाला देश है तथा इंडोने शया (73) और वयतनाम (69) के लगभग बराबरी पर है। इस सुधार का काफी श्रेय श्रम नियमों में कुछ बदलाव के अलावा वस्तु एवं सेवा कर तथा ऋणशोधन अक्षमता एवं दवा लया संहिता जैसे सुधारों को भी जाता है। यही वजह है क छह प्रमुख क्षेत्रों कारोबार की शुरुआत, ऋण तक पहुंच , निर्माण अनुमति, बिजली की उपलब्धता , कर चुकता करने और सीमापार

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 11, November- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

कारोबार, सभी में सुधार देखने को मला है। चालू वर्ष की शुरआत में वश्व बैंक के तत्कालीन मुख्य अर्थशास्त्री पॉल रोमर (जिन्हें हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल मला है) ने कारोबारी सुगमता रैं कंग की वश्वसनीयता को लेकर बहस छेड़ दी थी। रैं कंग में भारत का सतत सुधार ही देश में सुधारों की गति की वश्वसनीयता का सबसे बड़ा जवाब है।

वर्ष 2017 के एचडीआई सूचकांक में शा मल 188 देशों में से भारत की रैं कंग 130 है जब क 2015 में यह 131वें स्थान पर था। इस तरह भारत की एचडीआई रैं कंग में बहुत मामूली सुधार हुआ है। भारत का एचडीआई सूचकांक 0.63 से बढ़कर 0.64 हो गया, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 68.3 वर्ष से बढ़कर 68.8 वर्ष हो गई , स्कूली शक्षा में बिताए जाने वाले औसत वर्ष 6.3 से बढ़कर 6.4 हो गए और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) 5691 से बढ़कर 6363 डॉलर हो गया। 2012-17 के दौरान भारत की एचडीआई रैं कंग में केवल दो स्थान का सुधार हुआ है ले कन तुलनात्मक सुधार के मामले में द क्षण अफ्रीका (6), चीन (7) और ब्राजील (7) उससे आगे हैं।

जाली नोटों और आतंकवाद पर प्रहार

आरबीआई डेटा के मुताबिक, 2017-18 के दौरान बैं कंग सस्टम में 5 लाख 22 हजार 783 जाली नोटों का पता चला। यानी, कुल नोटों में पकड़े गए जाली नोट का प्रतिशत 36.1 रहा जो 2016-17 में महज 4.3 प्रतिशत था।नोटबंदी के बाद हवाला लेनदेन में काफी कमी है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि सेएक महत्वपूर्ण सफलता जी की वामपंथी चरमपं थयों और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को फं डंग अ धकतर हवाला के जरिए नगदी में होते थे।

मुद्रा आपूर्ति

वमुद्रीकरण/ नोटबंदी का एक प्रमुख उद्देश्य था वत्तीय तंत्र में करेंसी के प्रयोग को कम करना ।वस्तुतः करंसी अनाम होती है इसे जमा कया जा सकता है और ब्लैक मनी या काले धन के रूप में प्रयोग कया जा सकता है । इस लए सामान्यतया सरकार नहीं चाहती की मुद्रा को लोग नगदी के रूप में रखें।अक्टूबर 2016 में वमुद्रीकरण से पहले जनता के पास जो मुद्रा चलन में थी वह कुल मुद्रा आपूर्ति का 13.7 प्रतिशत थी ।मुद्रा आपूर्ति में जनता के पास रखी मुद्रा , बैंकों के पास रखी मांग ज माएंऔर साव ध जमाऐं सम्मि लत होती हैं, जिसे भारत में M3 कहा जाता है और भारत में यह मुद्रा आपूर्ति की व्यापक परिभाषा है।। वमुद्रीकरण के बादजनता के पास रखी मुद्रा में बहुत तेज गरावट आई और दिसंबर 2016 तक कुल मुद्रा आपूर्ति का घटकर 6.55 प्रतिशत हो गई।2 वर्ष बाद अक्टूबर 2018 मेंजनता के पास मुद्रा कुल मुद्रा आपूर्ति का लगभग 13 प्रतिशतथी हालां क यह वमुद्रीकरण से पहले के स्तर से कमहै।

नए नोटों की छपाई का खर्च ज्यादा

आरबीआई ने नोटबंदी के बाद 500 रुपये और 2,000 रुपये को नए नोट छापने पर 7,965 करोड़ रुपये खर्च कए। पछले वर्ष नोट छापने पर आधे से भी कम 3,421 करोड़ रुपये ही खर्च हुए थे। वत्त वर्ष 2017-18 में नोट छपाई पर 4,912 करोड़ रुपये खर्च हुए। प्रंटिंग और दूसरी लागत में वृ द्ध का असर

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 11, November- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

आरबीआई द्वारा सरकार को दिए जाने लाभांश पर पड़ा। केंद्रीय बैंक ने कहा क वत्त वर्ष 2016-17 में उसकी आमदनी 23.56 प्रतिशत घट गई जब क व्यय यानी खर्च दोगुने से भी ज्यादा 107.84 प्रतिशत बढ़ गया।

हां यह जरूर महत्वपूर्ण है की नए नोटों की प्रंटिंग में आरबीआई को काफी कसरत करनी पड़ी और इन नोटों की छपाई और ढूलाई में बहुत पैसे बर्बाद हुए और इस कारण सरकार को होने वाले लाभांश में महत्वपूर्ण कमी हुई । यह 2015 - 16 के वत्तीय वर्ष में 65876 करोड रुपए से घटकर 2017 -18 के वत्तीय वर्ष में 30659 करोड रूपया हो गया । नोटबंदी के कारण लोगों को असु वधा हुई जो उनका काम छोडकर बड़ी बड़ी लाइनों में लगना पड़ा, अगर इनकी लागत निकाली जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं है ।लाखों लोगों ने जो मान सक त्रास सहें है इस दौरान उसकी कोई लागत और कीमत नहीं है ।

लघु और मध्यम उद्योग प्रभावित

वमुद्रीकरण से सबसे अ धक लघु और मध्यम उद्योग प्रभा वत हुए क्यों क उनके व्यवसाय का ज्यादातर हिस्सा नकदी में होता है। परन्तु समय के साथ इन उद्योगों को बदलना ही होगा । यह असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के औपचारिक या संगठित क्षेत्र में बदलने का संक्रमण काल है जिसमे काफी गहरे संरचनात्मक परिवर्तन होने की संभावना है जो आगे चलकर अर्व्यव्स्था को मजबूती प्रदान करेगी। स्पष्ट है क वमुद्रीकरण से जनधन योजना के खाते और रुपे डे वट कार्ड की स क्रयता में वृ द्ध हुई है और ग्रामीण अर्थव्यस्था का मुद्रीकरण बढ़ा है।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष पहल

देश में असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र, जिसका सकल घरेलु उत्पाद में 40 प्रतिशत हिस्सा है, वमुद्रीकरण से प्रभा वत हुआ और इसकी वृ द्ध दर में और कमी हुई है। परन्तु इससे अनौपचारिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन संभा वत हैं और वह तेजी से औपचारिक या संगठित क्षेत्र में बदलने की ओर अग्रसर होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत सप्ताह सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लए 12 पहल वाले पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में वे उपाय शा मल हैं जो एमएसएमई की नए दौर में प्रवेश करने में मदद करेंगे। संक्षेप में कहा जाए तो ये उपाय न केवल इस क्षेत्र के लए ऋण की उपलब्धता बढ़ाएंगे बल्कि उनके लए कारोबार को और सुगम भी बनाएंगे। बीते दो वत्त वर्ष के दौरान एमएसएमई क्षेत्र को नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्रयान्वयन के रूप में लगातार दो झटके लगे। इनकी वजह से इस क्षेत्र की आय में काफी कमी आई। देश के गैर बैं कंग वत्तीय कंपनी क्षेत्र का मौजूदा संकट जो आईएलऐंडएफएस की कमजोरी की वजह से पैदा हुआ है , उसने भी एमएसएमई को ऋण का प्रवाह बा धत कया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह अच्छी बात है क सरकार अर्थव्यवस्था के इस अहम क्षेत्र की पूरी मदद कर रही है। देश में करीब 6.5 करोड़ ऐसे उद्यम हैं

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 11, November- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

जिन्होंने 12 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। यह रोजगार तैयार करने वाला कृ ष के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है।

नकदी के संकट से जूझ रहे इस क्षेत्र को तत्काल और तेजी से सहायता उपलब्ध कराने के लए प्रधानमंत्री ने एक देशव्यापी वेब पोर्टल की शुरुआत करने की घोषणा की जहां एक करोड़ रुपये तक का ऋण केवल एक घंटे से भी कम समय में जारी कया जाएगा। पहले चरण में सरकार 78 एमएसएमई क्लस्टर में पांच सरकारी बैंकों में इसे अंजाम देगी। बैंक अ धकारियों को इन जगहों पर तैनात कया जाएगा ता क ऋण आसानी से दिया जा सके। इसके बाद उन एमएसएमई को ऋण में दो प्रतिशत की छूट और नया ऋण दिया जाएगा जो जीएसटी के तहत पंजीयन करा चुके हैं। पैकेज में उन निर्यातकों को ब्याज में छूट देने की बात भी कही गई है जो माल भेजने के पहले और बाद में ऋण लेते हैं। ऋण आसान करने के अलावा पैकेज का ध्यान कारोबारी व्यवहार्यता बेहतर बनाने पर भी है। इसके लए सभी सरकारी उपकमों से कहा जाएगा क वे अपने कच्चे माल का 25 प्रतिशत एमएसएमई से खरीदें। पहले यह सीमा 20 प्रतिशत थी। इसी प्रकार 500 करोड़ रुपये से अ धक कारोबार करने वाली सरकारी कंपनियां और कारोबारी घरानों को अनिवार्य तौर पर ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डस्काउंटिंग सस्टम पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। इस कदम से उद्य मयों को अपनी आगामी प्राप्तियों के आधार पर बैंकों से ऋण मल सकेगा। इतना ही नहीं एमएसएमई को तकनीकी उन्नयन का समर्थन भी मलेगा। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण मंजूरी, निरीक्षण और रिटर्न फाइल करने की प्र क्रया को और सहज बनाए जाने की बात कही। कंपनी अ धनियम में संशोधन के लए अध्यादेश को मंजूरी दी जा चुकी है ता क कारोबारियों को अनावश्यक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।

सरकार को परेशानियों का अंदाजा था

नोटबंदी एक अच्छे मकसद से उठाया गया कदम था। नोटबंदी/ वमुद्रीकरण से लोगों को परेशानी होगी इसका अंदाजा था सरकार को ।तैयारी भी थी ले कन, पर कई कारणों से तैयारी अपर्याप्त रही ।और लोगों को अपने मेहनत के पैसे के लए भी मेहनत करनी पड़ी!गरीब, मजदुर, कामगार अस्थायी आय वाले लोगों ने नोटबंदी के बाद काफी कष्ट उठाए हैं। परन्तु बड़ा परिवर्तन बिना कष्ट के नहीं आता। वमुद्रीकरण सरकार द्वारा काला धन की समाप्ति और अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लए उठाये जाने वाले व भन्न क़दमों की श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी मात्र थी। इस लए अर्थव्यवस्था और समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभावों को बिलकुल अलग से देखना और जल्दबाजी में इसका मूल्याङ्कन करना सही तस्वीर सामने नहीं लायेगा।

लोकलुभावन नहीं बल्कि कठोर क़दमों के द्वारा ही दीर्घाव ध प्रभाव वाले बदलाव लाये जा सकते हैं।आ र्थक प्रभावों का सही-सही अनुमान बहुत कठिन है! काला धन और जाली नोटों की सफाई लए कये गए इस वमुद्रीकरण का व्यावहारिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव और भी अ धक महत्वपूर्ण है।यह

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 11, November- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

जनता, कारोबारियों, भ्रष्टाचारियों और निवेशकों के लए एक ठोस औरस्पष्ट संकेत है क सरकार अर्थव्यवस्था की ओवरहा लंग,कायाकल्प के लएप्रतिबद्ध है।

सबसे महत्वपूर्ण हैं वहभय जो क इस समय काला धन रखने और सृजित करने वाले लोगों के दिलो दिमाग मेंअब भी बना हुआ है; यह एहसास क समस्त आय का हिसाब- कताब होना जरुरीहै ; यह समझ क बैक खाता होना और बैं कग की आदत डालना महत्वपूर्ण है। यह डजिटल भारत की ओर बढ़ते कदम हैं जो क अर्थव्यवस्था को एक नया स्वरूप औरमजबूती प्रदान कर रहे हैं । यह असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र की ओर तेजी सेबदलने का भी एक संकेत है। वमुद्रीकरण की यह सबसे बड़ी सफलता है! कहा जाता है, जहाँ 3 अर्थशास्त्री होते हैं वहां 4 राय होती है!एक प्र सद्द अर्थशास्त्री ने कहा है क हम अर्थव्यवस्था की कोई योजना नहीं बना सकते; यह एक जटिल कार्य है क्यों क कोई योजना बनाने के लए जो पर्याप्त सूचना चाहिए होती है वह प्राप्त करना बेहद मुश्किल है । वास्तव में अर्थव्यवस्था में कसी भी परिवर्तन का प्रभाव आकस्मिक होता है जो क स्वयं सस्टम से ही उत्पन्न होता है । सस्टम द्वारा परिवर्तन की स्वीकार्यता,ग्राह्यता और सस्टम के सभी अंगों को इस परिवर्तन के अनुकूल बनाने में लगा समय महवपूर्ण है । कसी भी योजना की सफलता उसके क्रयान्वयन पर तथा क्रयान्वित और निगरानी करने वाले अ धकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता , ईमानदारी और प्रतिबद्धता पर भी निर्भर करती है। नोट बंदी की कुछ मोर्चो पर अ सफलता के लए काफी हद तक योजना का क्रयान्वयन और भ्रष्टाचार जिम्मेदार रहा है।

नोट बंदी ने काले धन को गोबर बना दिया। नोट बंदी का प्रभाव मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था और समाज पर सकारात्मक पड़ा है। नोटबंदी अर्थव्यवस्था के लए शॉक ट्रीटमेंट की तरह था। प्रत्येक बड़े काम के अच्छे बुरे परिणाम दोनों होते हैं। परंतु 40 प्रतिशतनिष्क्रिय पड़ी मुद्रा के चलन में आने से बैंकों के पास तरलता में वृ द्ध हुई और वह वकास के लए अ धक ऋण देने में सक्षम हो पाए ।समाज में और लोगों पर यह भय क गलत कार्य करने पर पकड़े जा सकते हैं नोट बंदी की एक बड़ी सफलता है । भ्रष्टाचार का जिस तरह से संस्थानिकरण हुआ है उसके कारण नोट बंदी का अपे क्षत परिणाम नहीं आ पाया। जब तक लोगों के माइंडसेट में परिवर्तन नहीं होता या उन में नैतिकता का समावेश नहीं होता है तब तक इस तरह के कड़े कदमों का ठोस परिणाम सामने नहीं आ सकता। नोट बंदी से पहले सरकार को सबसे अ धक रोजगार प्रदान करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र और खुदरा और छोटे व्यापारियों पर इसके प्रभाव के संदर्भ में गंभीरता से सोचना चाहिए था।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 11, November- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

सन्दर्भ :

- Two years after demonetization: A look at what has happened so far (2018) indianexpress.com/article/india/demonetisation-second-anniversary-congress-bjp-5437069/November 8, 2018
- Liz Mathew Liz (2018): Demonetisation has unmasked urban naxals, says BJP think-tank study
- https://indianexpress.com/article/india/demonetisation-has-unmasked-urban-naxals-says-bjp-think-tank-study/ November 1, 2018
- Bandyopadhyay, Tamal (2017): From Lehman to demonetization: A decade of disruptions, reforms and misadventures; Portfolio, Penguin Random House India, pp. 238- 249
- Agarwala, Ramgopal (2017): Demonetisation: A means to an end ?; SAGE India
- Sanyal, Meera H. (2018): The Big Reverse; Harper Business, India